



04 - आतंकवाद की ओट में निर्दोषों पर अत्याचार की बारी



05 - लोकतंत्र का मंदिर और संविधान की आस्था का केंद्र मध्यप्रदेश विधानसभा

A Daily News Magazine

इंदौर
मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 79, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



06 - यातायात पुलिस ने 11 महीने में बिना हेल्मेट 3556 वाहनों के बनाये...



07 - चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे म.प्र. के 648...



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

जब कभी चाहो मुझे दूढ़ना तो दूढ़ना उदास सी शाम में जब ढलता हो सूरज और गहराती हो लालिमा और लौट रहे हों पंछी अपने घरों को जब कभी चाहो मुझे दूढ़ना तो दूढ़ना समुंदर के साहिलों पर उठती-गिरती लहरों साथ जो बेबस लौट जाती हैं, बार-बार जब कभी चाहो मुझे दूढ़ना तो दूढ़ना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ दूर क्षितिज को ताकते जहां आलिंगनबद्ध होते हैं धरती और गगन जब कभी चाहो मुझे दूढ़ना तो मैं मिल्गी, पतझड़ में झड़ते पत्तों संग भीगती हुई बारिशों संग कांस के रुओं की तरह सेमल की रुई की तरह उड़ती हुई और आ आ कर तेरी शर्ट से चिपकती हुई गर कभी तुम चाहो मुझे दूढ़ना।

- निरुपमा खरे

प्रसंगवश

जगदीप सिंधु

मेरा तो कलेजा कांप उठता है, यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40 प्रतिशत जनता झुगियों में रहती है, तब कोई सीएम कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। शीला दीक्षित जी के आधिकारिक आवास में लगे 10 AC के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कौन भरता है इन सब का बिल? मैं और आप भरते हैं।

6 स्टाफ रोड बंगले की हकीकत अब सब के सामने है। खुद को आम आदमी बताकर कभी बंगला और कार नहीं लेने की बात कहकर सत्ता में आए मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास में लगे सामान की सूची सार्वजनिक होते ही इसकी भव्यता जानकर सब हैरान हैं। 9 साल तक केजरीवाल इस बंगले में रहे हैं। मुख्यमंत्री पद त्यागने के बाद यह बंगला खाली करना पड़ा है।

अत्रा हजारे आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर 2012 में एक नयी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर नए तरह की राजनीति करने के ख्वाब पुरे देश को भी दिखाए गए थे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से मुक्त एक पार्टी की कल्पना ने अधिकांश उदार विचारधारा को मानने वाली जनता को अपनी ओर खींचा और भरपूर समर्थन पाया। जड़ भ्रष्ट अलोकतांत्रिक एकाधिकारवादी राजनीति के विपरीत एक प्रगतिवादी भागीदारी व सुगम कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था आधारित राजनीति को विकल्प के रूप में स्थापित करने के संदेश और लक्ष्य में ढाल कर बनायी आम आदमी पार्टी को केजरीवाल ने धीरे-धीरे पूरी तरह से अपनी महत्वाकांक्षा के इर्दगिर्द ही समेट

लिया।

जनता के विश्वास ने 2013 के दिल्ली विधानसभा के पहले ही चुनाव में 29.48 प्रतिशत मत और 70 में से 28 सीट पार्टी की झोली में डाल दिए और आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन कर उभरी। भाजपा को 33 प्रतिशत मत हासिल कर 31 सीट जीती तो कांग्रेस ने भी 24.6 प्रतिशत मत हासिल किये और 8 सीटों पर सिमट गयी थी। बहुजन समाज पार्टी को 5.35 प्रतिशत ही मत मिल सके थे। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने।

भाजपा ने दिल्ली के चारों ओर बाहरी क्षेत्रों में सफलता हासिल की थी तो आम आदमी पार्टी ने मध्य दिल्ली के क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई। 66 व मतदान हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटों पर चुनाव लड़ा 32.9 व मत हासिल किये लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अरविन्द केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबले में बुरी तरह मात खा गए।

2015 में एक साल के राष्ट्रपति शासनकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के 15 प्रतिशत वोट भी आम आदमी पार्टी की ओर चले गए और कांग्रेस के पास केवल 9.7 प्रतिशत ही मत रह गए। दिल्ली की जनता ने 54.3 प्रतिशत के बड़े समर्थन से 67 सीट पार्टी की झोली में डाली। भाजपा को केवल 3 सीट ही मिली, लेकिन उसका मत 32.3 प्रतिशत रहा।

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 53.57 प्रतिशत मत आम आदमी पार्टी को मिले लेकिन अबके सीटें कम हो गईं। 62 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की लेकिन भाजपा के मत में लगभग 6.2 प्रतिशत

(38.51 प्रतिशत) की बढ़ोतरी से सीटों का ग्राफ बढ़ कर 8 पहुँच गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का मत 2019 के मुकाबले 32.9 प्रतिशत से घट कर 24.17 प्रतिशत आ गया। दिल्ली विधान सभा चुनावों में अबकी बार आम आदमी पार्टी के कई नेता चिंता में घिरे हुए हैं कि कई मुद्दों की वजह से जनता में लोकप्रियता की कमी मत प्रतिशत कितना अंतर डालेगी।

एक दशक बीत जाने के बाद भी पार्टी को पूरी तरह संरचना में नहीं ढाला गया बल्कि पूरा वर्चस्व केवल एक व्यक्ति केंद्रित ही बना हुआ है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राष्ट्रवाद के समांतर हिंदुत्व की पहचान को निरंतर बनाए रखा गया है। दिल्ली के स्कूल पाठ्यक्रम में देशभक्ति के अध्याय जोड़ने और खुद को हनुमान भक्त घोषित करने के यत्न इसी कड़ी का अंग हैं। विभिन्न सम्प्रदायों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए साथ जरूर लिया गया लेकिन धर्मानरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत को स्पष्टता से स्थापित करने के लिए गंभीर संघर्ष करने में प्राथमिकता तय नहीं की गई।

आज आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी के सामने उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो एक समय में पार्टी के गठन का आधार बने थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है और कई वादे अधूरे रह गए हैं। यमुना को स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर पाए। यमुना नदी अब पहले से भी अधिक प्रदूषित है। हर साल प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता को जो दंश झेलना पड़ता है उसका कोई स्थाई समाधान केजरीवाल सरकार अभी तक खोज नहीं पायी।

जो बुनियादी सेवाओं को देने का जोर शोर से प्रचार

किया गया था अभी तक वैसी बुनियादी सेवाएं दे पाने के स्तर तक नहीं पहुँच पाए। उपराज्यपाल से तकरार और एकराव के चलते दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं।

केजरीवाल के नए बंगले की भव्यता उजागर होने के बाद और बंगले में हुए स्वाति मालीवाल जैसे कई विवादलोक सभा चुनाव में अन्य राज्यों में प्रचार के लिए पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग है, जो लोगों को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या अब भी केजरीवाल आम आदमी हैं या नहीं। यह साफ है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में लगाती रहेगी तो दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के चुनाव में राज्य की तस्वीर बदलने के लिए एक मौका मांग कर सत्ता में आयी आम आदमी पार्टी की हालत किये गए वादे पूरे नहीं कर पाने के चलते कमजोर ही मानी जाने लगी है।

अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के आम लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू करने वाले और ऐसा करना जारी रखने की कसम उठाने वाले केजरीवाल की प्राथमिकताएं बदलते हुए दिल्ली देख रही है। भाजपा सरकार द्वारा प्रताड़ित किये जाने की सहानुभूति के प्रयोग करने की रणनीति पर चुनाव में केजरीवाल अपना दांव मजबूत करने में लगे हैं।

राजनीति में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा के शीशमहल की कोमल चांदनी नहीं बल्कि त्याग की कड़ी धुप में झुलसना होता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू

खाद संकट पर कांग्रेस का वॉक आउट सदन में गलत उत्तर, दो पर कार्रवाई

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन रहा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में खाद संकट पर चर्चा कराने की मांग

थे। इसके बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना कि सदन में वृटिवश गलत जानकारी आ गयी थी राधोगढ कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम अभी संचालित नहीं है।



की जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने मामूली हंगामा कियों नेता प्रतिपक्ष की मांग को स्वीकारने स्वीकार नहीं किया इस पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया। ध्यानाकर्षण के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह और बुधनी से विधायक रमाकांत भागव के शपथ ग्रहण से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई।

इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने खाद की खाली बोरियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वे किसानों को खाद नहीं मिलने का मुद्दा उठा रहे

सदन की कार्यवाही से पहले बुधनी से भाजपा विधायक रमाकांत भागव और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विजयपुर से निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा सदन में नहीं पहुंचे, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ आज नहीं हो पाई।

पूर्व मंत्री कहा- अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर व्यापार चल रहा- पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए अपनी बात रखी।

संसद का शीतकालीन सत्र नहीं थम रहा हंगामा

● वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हुआ। वित्त मंत्री ने कहा- कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था।

इस पर खड़गे ने कहा, जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे, वे आज शिक्षा दे रहे हैं। जब संविधान बना, तो इन लोगों ने इसे जला दिया था। जिस दिन संविधान अपनाया गया था,



इन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली में बाबासाहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पुतले जलाए थे। आरएसएस के नेता संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा

- कांग्रेस जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहती है। धनखंड ने कहा, 'क्या होगा अगर कोई गब्बर सिंह आकर कहे कि मुझे बदनाम किया गया है।'
- कांग्रेस ने दवाकों तक पुराने संसद भवन के मध्य में बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाने दी, उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा गया।
- मजरुह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जेल भेजा गया था। क्योंकि इन लोगों ने नेहरू के खिलाफ कविता सुनाई थी।

पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर- नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाएं

इसमें एडविना, जेपी, आईस्टाइन को लिखी चिट्ठियां, 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में पीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाएं, या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे।

रिजवान ने कहा- सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर



लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था। हालांकि, इसकी जानकारी अब सामने आई है।

रिजवान ने जिन 51 बक्सों की बात कर रहे हैं, उनमें नेहरू के वे लेटर रखे हुए हैं, जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आईस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे।

● भाजपा बोली- ऐसा क्या था, जो गांधी परिवार देश को नहीं बताता चाहता- भाजपा सांसद संजिव पात्रा ने कहा कि उन लेटर में ऐसा क्या लिखा था, जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि वे बातें देश के सामने आएँ।

इस स्मारक में शुरू में सिर्फ नेहरू के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद थे, जिनमें नेहरू के वर्ल्ड लीडर्स को लिखे लेटर शामिल थे। बाद में पता चला कि 51 बक्सों ऐसे भी थे, जिनमें नेहरू के एडविना माउंटबेटन, जेपी नारायण और कई अन्य नेताओं को लिखे गए पत्र थे। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल वाकई सोनिया गांधी से बात करेंगे कि वे इन पत्रों को देश को वापस लौटा दें।

